खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
मई, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों की पहल के तहत आधार से जुड़ी बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सुविधाओं के साथ अब 3,16,987 (60%) उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। इस समय देश भर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग लगभग 83.5 प्रतिशत (परिवार का कम से कम एक सदस्य) तथा राशन कार्ड डाटा में लाभार्थी-वार आधार सीडिंग लगभग 73.64 प्रतिशत है।
- दिनांक 01.06.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक 680.25 लाख टन (242.70 लाख टन चावल तथा 437.55 लाख टन गेहूं) है, जो अनुकूल स्थिति है।
- विभाग वर्ष 2018-19 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से खुले बाजार में गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टाक की बिक्री के लिए नीति तैयार कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए गठित सचिवों की समिति ने 21.05.2018 को हुई बैठक में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। सिफारिशों पर माननीय मंत्री महोदय, (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद, अंतिम अनुमोदन हेतु माननीय वित्त मंत्री महोदय को भेजा जाएगा।
- चालू खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान दिनांक 04.06.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के रूप में 57.08 लाख टन धान की खरीद की गई है, जबकि खरीफ विपणन मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 56.06 लाख टन की खरीद की गई थी।
- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान देश के अन्य भागों में खरीद तेजी से हुई है, जिसमें 430 लाख टन के लक्ष्य के प्रति धान के रुप में 352.26 लाख टन चावल की खरीद (दिनांक 30.05.2018 की स्थिति के अनुसार) पहले ही कर ली गई है। रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन के लक्ष्य के प्रति 341.53 लाख टन गेहूं की खरीद (30.05.2018 तक) पहले ही कर ली गई है।
- भारतीय खाद्य निगम की पुन: संरचना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रगति निम्नानुसार है:

(क) डिपो ऑनलाईन प्रणाली फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के सभी 530 डिपुओं में प्रचालनरत है। केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में, डिपो ऑनलाईन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए सभी 156 डिपुओं में कार्यान्वित की गई है।

(ख) जहां तक आधुनिक साईलोज के निर्माण का संबंध है, 84 स्थानों पर कुल 44 लाख टन क्षमता के लिए साइलो ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर 6.25 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, 5.50 लाख टन क्षमता के लिए निविदाएं सौंपी गई हैं।

- चीनी मिलों को किसानों के देय गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने चीनी कारखानों को गन्ना लागत की भरपाई करने हेतु चीनी मौसम 2017-18 के दौरान पेराई किए गए गन्ने पर 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 09.05.2018 को एक स्कीम अधिसूचित की है। उक्त सहायता राशि का भुगतान मिलों की ओर से किसानों को सीधे ही किया जाएगा तथा इसे उचित और लाभकारी मूल्य के प्रति किसानों को देय गन्ना मूल्य के प्रति समायोजित किया जाएगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित बकाया राशि भी शामिल होगी।
- चीनी मौसम 2017-18 के लिए, 31.05.2018 की स्थिति के अनुसार देय कुल 82819 करोड़ रुपए की गन्ना मूल्य की राशि में से 60153 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है और 22666 करोड़ रुपए की गन्ना राशि बकाया है।

****